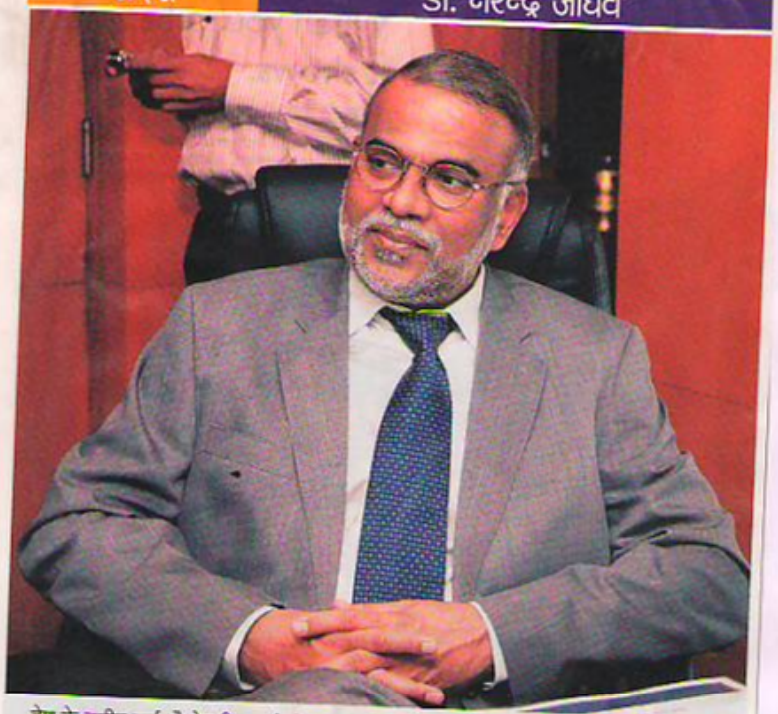

इंडिया प्राइड अॅवार्ड
9 अक्टूबर २०१०
दैनिक भास्कर (विशेष पुरस्कार पुरवणी

संदेश

डा. नरेन्द्र जाधव

देश के करीब ढाई सौ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न राज्यों के करीब 850 सार्वजनिक उपक्रमों में से इने गिने उपक्रमों को चुनना, ये बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन इस दुरूह कार्य को भी आसान बनाया इंडिया प्राइड अवार्ड्स ने।

प्रबंधन ने दैनिक भास्कर समूह को इंडिया प्राइड अवार्ड्स की स्थापना के लिए बधाई देता हूं। इस माध्यम द्वारा दैनिक भास्कर ने सरकारी कंपनियों की बेहतरी को सामने लाने का प्रयास किया है। देश के करीब ढाई सौ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न राज्यों के करीब 850 सार्वजनिक उपक्रमों में से इने गिने उपक्रमों को चुनना, ये बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन इस दुरूह कार्य को भी आसान बनाया इंडिया प्राइड अवार्ड्स ने। सबसे पहले तो कंपनियों से सूची मंगवाई गई और उनसे दी गई सूचनाओं के आधार पर अधिक अनुसंधान करने वाली नामी संस्था से कंपनियों का विश्लेषण किया फिर यही आकर उस लिस्ट सामने आया। इस कार्य के लिए मैं संस्था को भी बधाई देता हूं। संस्था ने सभी टीमें कार्य का सही सही मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार किया। संस्था की रिपोर्ट के आधार पर ही जूरी के सदस्यों ने बैठक की। जूरी के सदस्यों को देखा जाए तो इनमें अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें डा. यू.डी. चौबे और [illegible] जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल थे, साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र के लीडर के.यू. राव भी थे। मीडिया एवं एडवर्टाइजिंग जगत के जाने माने व्यक्ति संदीप गोयनका थे, दूसरी तरफ एकेडेमिशियन और चैरिटेबल विशेषज्ञ जगत के सदस्य शामिल थे। कंपनियों के आर्थिक और तकनीकी पहलुओं के जानकार एन. शिवकुमार भी जूरी में शामिल थे। जूरी के सदस्यों ने संस्था की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न कंपनियों के कार्य निष्पादन और अन्य मसलों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से अंतिम फैसला सुनिश्चित किया।

आमतौर पर देखा गया है पीएसयू कंपनियां देशभर में काम करती तो आती रही हैं। जिनमें अवार्ड के लिए अपनी तरफ से पहल करने में वे संकोच महसूस करती हैं। दैनिक भास्कर समूह का यह प्रयास बेहद सराहनीय है कि अब पीएसयू की तरफ से काफी दूरी आ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि वर्ष 2009 में हुए इंडिया प्राइड अवार्ड के मुकाबले इस वर्ष एंट्री की संख्या दुगुनी हो गई। यह बड़ी बात है। सरकारी कंपनियों को भी अब लगता है कि इनमें भाग लेना चाहिए जो काम न करें उनके अपने हित में और अंततः देश के हित में है। (डा. नरेन्द्र जाधव इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2010 की जूरी के अध्यक्ष थे। वह योजना आयोग के सदस्य होने के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं।)